

प्रेषक,

एम. रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. संमस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
2. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून, दिनांक: 04 जुलाई, 2006

विषय: गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के कृषक मजदूरों/भूमिहीन कृषकों के आर्थिक विकास हेतु कृषि भूमि को क्रय करके उन्हें उपलब्ध कराने की योजना के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक रूपरेखाएँ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के खेतीहर मजदूरों/भूमिहीन कृषकों के आर्थिक विकास हेतु कृषि भूमि को क्रय करके उन्हें उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उनकी आय में बढ़ोत्तरी की जा सके तथा उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के लिए कारगर प्रयास किये जा सकें।

2- योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन, योजना की स्वीकृति, क्रय कर आबंटित की जाने वाली कृषि भूमि का चयन एवं उसका क्रय मूल्य निर्धारित करने तथा प्रश्नगत धन के व्यय की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक जनपदीय समिति का गठन किया जायेगा :

क्रमशः 2 पर

- 9- जहां तक सम्भव हो ऐसी भूमि क्रय की जाए, जो कि लाभार्थियों के निवास के निकट हो और यथासम्भव भूमि का एक बड़ा चक क्रय किया जाए ताकि एक स्थान पर उसे अधिक से अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित किया जा सके। इसका यह लाभ होगा कि आबंटियों को भूमि पर कब्जा करने में आसानी होगी और आबंटियों को सामूहिक कृषि विकास की योजनाओं से भी लाभान्वित कराने में सुविधा होगी।
- 10- भूमि क्रय के साथ ही व्यय का लेखा-जोखा तथा सम्पत्ति रजिस्टर, जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण, विक्रेता का नाम, आबंटियों का नाम, आबंटन का दिनांक, दाखिल खारिज का दिनांक आदि पूर्ण विवरण अंकित होगा, का रख रखाव जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 11- लाभार्थियों को दी जाने वाली योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए उनसे अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायेगा।
- 12- अनुबन्ध पत्र तथा आबंटन पत्र का प्रारूप पृथक से प्रेषित किया जायेगा।
- 13- जब तक आय-व्यय में पृथक से व्यवस्था नहीं हो जाती है, इस योजना का क्रियान्वयन 'अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता' की मद से किया जायेगा।
- 14- योजना का तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त योजना को तत्परता से क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि समस्त जिलाधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शासन को अवगत करायेंगे कि उनके जनपद में अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले कितने कृषक मजदूर/भूमिहीन कृषक हैं तथा उनके लिए उक्त

9- जहां तक सम्भव हो ऐसी भूमि क्रय की जाए, जो कि लाभार्थियों के निवास के निकट हो और यथासम्भव भूमि का एक बड़ा चक क्रय किया जाए ताकि एक स्थान पर उसे अधिक से अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित किया जा सके। इसका यह लाभ होगा कि आबंटियों को भूमि पर कब्जा करने में आसानी होगी और आबंटियों को सामूहिक कृषि विकास की योजनाओं से भी लाभान्वित कराने में सुविधा होगी।

10- भूमि क्रय के साथ ही व्यय का लेखा-जोखा तथा सम्पत्ति रजिस्टर, जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण, विक्रेता का नाम, आबंटियों का नाम, आबंटन का दिनांक, दाखिल खारिज का दिनांक आदि पूर्ण विवरण अंकित होगा, का रख रखाव जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

11- लाभार्थियों को दी जाने वाली योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए उनसे अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायेगा।

12- अनुबन्ध पत्र तथा आबंटन पत्र का प्रारूप पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

13- जब तक आय-व्यय में पृथक से व्यवस्था नहीं हो जाती है, इस योजना का क्रियान्वयन 'अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता' की मद से किया जायेगा।

14- योजना का तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त योजना को तत्परता से क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि समस्त जिलाधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शासन को अवगत करायेंगे कि उनके जनपद में अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले कितने कृषक मजदूर/भूमिहीन कृषक हैं तथा उनके लिए उक्त

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (1) | जिलाधिकारी | : अध्यक्ष |
| (2) | मुख्य विकास अधिकारी | : सदस्य |
| (3) | अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) /
अपर जिलाधिकारी | : सदस्य |
| (4) | सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार | : सदस्य |
| (5) | मुख्य कृषि अधिकारी | : सदस्य |
| (6) | जिला उद्यान अधिकारी | : सदस्य |
| (7) | सम्बन्धित तहसील के अधिशासी
अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग | : सदस्य |
| (8) | सम्बन्धित तहसील के सहायक
अभियन्ता, लघु सिंचाई | : सदस्य |
| (9) | जिला समाज कल्याण अधिकारी | : सदस्य सचिव |

3- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषक मजदूर होंगे।

4- लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता तथा कृषि कार्य में रुचि के आधार पर जनपदीय समिति द्वारा किया जायेगा।

5- योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को लगभग 0.50 एकड़/0.20 है० कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

6- भूमि क्रय के लिए पूर्ण क्रय मूल्य, जो जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा, लाभार्थी को अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

7- योजना का कार्यान्वयन जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, परन्तु योजना के कार्यान्वयन एवं धन की स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही जनपदीय समिति द्वारा की जायेगी।

8- भूमि का क्रय समाज कल्याण विभाग द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के नाम से किया जाएगा तथा भूमि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज कराई जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भूमि क्रय की कार्यवाही के तुरन्त बाद लाभार्थी को आबंटित कर दी जायेगी।

क्रमशः 3 पर